कंपनियों की सेहत सुधरने से बढ़ा सीएसआर

यूपी की ऊंची छलांग : नौ साल में 12वें से सीधे 5वां स्थान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में कारोबारी माहौल बनने के बाद कंपनियों की सेहत में सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (सीएसआर) यानी कॉर्पोरेट जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व फंड बढ़ गया है। यूपी इस मामले में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। जबकि, नौ साल पहले यह फंड प्राप्त करने में यूपी 12वें स्थान पर था। एक साल में प्रदेश में 1321 करोड़ रुपये सीएसआर फंड के तहत सामाजिक कार्यों में खर्च किए गए। जबकि 2015 में महज 148 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

देश में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हर कंपनी सीएसआर के दायरे में नहीं आती। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिनका एक हजार करोड़ का टर्न ओवर हो या एक साल में पांच करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो, उन्हें अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। इस फंड का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत, सामाजिक न्याय आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है।

राज्य	फंड
महाराष्ट्र	5229.31
कर्नाटक	1761.39
गुजरात	1554.16
तमिलनाड	1371.91
उत्तर प्रदेश	1321.36
दिल्ली	1158
राजस्थान	700

यूपी में साल-दर-साल बढ़ा सीएसआर

वर्ष	फंड
2017-18	435.21
2018-19	521.32
2019-20	577.98
2020-21	907.32
2021-22	1321.36

करोड़ रुपये में

- सीएसआर फंड तभी बढ़ता है, जब कंपनियों की आय बढ़ती है। प्रदेश में सीएसआर गतिविधियों में खर्च बढ़ने का सीधा संकेत है कि यहां की कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है।